गरवी गुजरात

TITLE CODE:- UPHIN51504

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 233
दि. 24.12.2025,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : ASHWANI KUMAR Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

राष्ट्रपति ने 'जन-केंद्रित राष्ट्रीय सुरक्षा : विकसित भारत के निर्माण में सामुदायिक भागीदारी' विषय पर आईबी शताब्दी वृत्ति व्याख्यान को संबोधित किया

■ आर्थिक निवेश और विकास के प्रमुख संचालकों में सुरक्षा भी शामिल हैः राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

■ जन कल्याण और जनभागीदारी को रणनीति के केंद्र में रखकर, हम अपने नागरिकों को खुफिया जानकारी और सुरक्षा के प्रभावी स्रोत बनने के लिए सशक्त बना सकते हैंः राष्ट्रपति

(जीएनएस)।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (23 दिसंबर, 2025) नई दिल्ली में 'जन-केंद्रित राष्ट्रीय सुरक्षाः विकसित भारत के निर्माण में सामुदायिक भागीदारी' विषय पर आईबी शताब्दी वृत्ति व्याख्यान को संबोधित किया।

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि यह गर्व की बात है कि स्वतंत्रता के बाद से, आईबी देश के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने में एक उत्कृष्ट भूमिका निभा रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि इस व्याख्यान का विषय 'जन-केंद्रित राष्ट्रीय सुरक्षाः विकसित भारत के निर्माण में सामुदायिक भागीदारी' हमारे देश के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों नजरिए से महत्वपूर्ण है। आईबी सहित सभी संबंधित संस्थानों को हमारे लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। जागरूक नागरिक राष्ट्रीय सुरक्षा में लगे सरकारी एजेंसियों के प्रयासों में सशक्त तरीके से मदद कर सकते हैं। एक समुदाय के रूप में संगठित होकर हमारे नागरिक बड़ा समन्वय कर सकते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार की पहलों में मदद कर सकते हैं। हमारा संविधान नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है। इनमें से कई कर्तव्य राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक आयामों से संबंधित हैं। छात्र, शिक्षक, मीडिया, निवासी कल्याण संघ, नागरिक समाज संगठन और कई अन्य समुदाय इन कर्तव्यों का प्रचार-प्रसार कर सकते हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती प्रदान करती है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें जागरूक नागरिक सुरक्षा संकटों को टालने में पेशेवर बलों की सहायता करने में आगे रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यापक परिभाषा और रणनीति में जनता को केंद्र में रखा गया है। जनता को अपने आसपास घटित घटनाओं का मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहिए।

उन्हें अपने परिवेश और आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा में जागरूक और सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। 'जन भागीदारी' जन-केंद्रित सुरक्षा की आधारशिला है।

राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी नागरिक पुलिस और आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों को जनता की सेवा की भावना से काम करना होगा। सेवा की यह भावना जनता में विश्वास पैदा करेगी। यह विश्वास जन-केंद्रित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति विकसित करने की पूर्व शर्त है, जिसमें सामुदायिक

भागीदारी एक महत्वपूर्ण तत्व होगी।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत बहुआयामी सुरक्षा चुनौतियों और खतरों का सामना कर रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव, आतंकवाद और उग्रवाद, विद्रोह और सांप्रदायिक कट्टरता पारंपरिक रूप से सुरक्षा संबंधी चिंता के विषय रहे हैं। हाल के वर्षों में, साइबर अपराध एक महत्वपूर्ण सुरक्षा खतरा बनकर उभरे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि देश के किसी भी हिस्से में सुरक्षा के अभाव का आर्थिक प्रभाव इससे प्रभावित क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक होता है। सुरक्षा, आर्थिक निवेश और विकास के प्रमुख कारकों में से एक है। 'समृद्ध भारत' के निर्माण के लिए 'सुरक्षित भारत' का निर्माण आवश्यक है।

राष्ट्रपति ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। उन्होंने बताया कि आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत बलों और एजेंसियों की गहन कार्रवाई वामपंथी उग्रवाद के लगभग उन्मूलन का प्रमुख कारण रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न पहलों के माध्यम से समुदायों का विश्वास जीतने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया। आदिवासी और दूरदराज के क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देना वामपंथी उग्रवादियों और विद्रोही समूहों द्वारा लोगों के शोषण के खिलाफ प्रभावी साबित हुआ है।

राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना और संचार की दुनिया को बदल दिया है। इसमें सृजन और विनाश दोनों की क्षमता है। लोगों को गलत सूचनाओं से बचाना एक बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस कार्य को निरंतर और अत्यंत प्रभावी ढंग से करना होगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया उपयोगकताओं का ऐसा सक्रिय समुदाय बनाने की आवश्यकता है जो लगातार राष्ट्रीय हित में तथ्यों पर आधारित जानकारी प्रस्तुत करे।

राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे जटिल चुनौतियां गैर-पारंपरिक और डिजिटल प्रकृति की हैं। इनमें से अधिकांश समस्याएं अत्याधुनिक तकनीकों से उत्पन्न होती हैं। इस संदर्भ में, तकनीकी रूप से सक्षम समुदायों को विकसित करने की आवश्यकता है। डिजिटल धोखाधड़ी से बचने के लिए घरेलू, संस्थागत और सामुदायिक स्तर पर सतर्कता आवश्यक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म नागरिकों को फिशिंग, डिजिटल धोखाधड़ी और ऑनलाइन दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए सशक्त बना सकते हैं। वे संबंधित एजेंसियों को वास्तविक समय का डेटा प्रदान कर सकते हैं। ऐसे वास्तविक समय के डेटा का विश्लेषण करके, भविष्यसूचक पुलिसिंग मॉडल विकसित किए जा सकते हैं। नागरिकों के सतर्क और सक्षम समुदाय न केवल साइबर अपराधों के प्रति कम संवेदनशील होंगे, बल्कि ऐसे अपराधों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में भी कार्य करेंगे।

राष्ट्रपति ने कहा कि जन कल्याण और जनभागीदारी को अपनी रणनीति के केंद्र में रखकर हम अपने नागरिकों को खुफिया जानकारी और सुरक्षा के प्रभावी स्रोत बनने के लिए सशक्त बना सकते हैं। जनभागीदारी से प्रेरित यह परिवर्तन 21वीं सदी की जटिल और बहुआयामी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहायक होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनभागीदारी के माध्यम से हम सभी एक सतर्क, शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे।

उपराष्ट्रपति ने 'सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि' पुस्तक का विमोचन किया

अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था थेः उपराष्ट्रपति

वाजपेयी के नेतृत्व में हुए पोखरण परमाणु परीक्षणों ने एक आत्मविश्वासी एवं पुनर्जीवित भारत को प्रदर्शित कियाः उपराष्ट्रपति

'अटल बिहारी वाजपेयी की सुशासन की विरासत भारत के विकास मार्ग को प्रेरित करती है'

(जीएनएस)।

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति निवास में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी द्वारा लिखित पुस्तक 'सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि' का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने श्री देवनानी को पुस्तक लिखने के लिए बधाई दी और इसे एक समयोचित एवं महत्वपूर्ण योगदान कहा, विशेषकर तब जब देश पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी मना रहा है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक व्यक्ति नहीं

बल्कि स्वयं में एक संस्था थे, जिनका जीवन और नेतृत्व सिद्धांतों एवं मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था।

उपराष्ट्रपति ने श्री वाजपेयी के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों को याद करते हुए कहा कि उन्हें 12वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में श्री वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए उनसे सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने जनसंघ के दिनों की सुखद यादें साझा कीं, जिनमें आपातकाल से पहले कोयंबटूर में श्री वाजपेयी के लिए एक बड़े सार्वजनिक सम्मेलन का आयोजन करना शामिल था, यह अनुभव उनके जीवन में गहरा एवं अमिट छाप छोड़ा।

राष्ट्रनिर्माण में श्री वाजपेयी के योगदान पर प्रकाश डालते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री वाजपेयी की दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को कई क्षेत्रों में रूपांतरित किया। मई 1998 में ऑपरेशन शक्ति के अंतर्गत पोखरण में सफल परमाणु परीक्षणों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि श्री वाजपेयी का निर्णायक नेतृत्व वैश्विक मंच पर भारत के आत्मविश्वास एवं संकल्प को प्रदर्शित करता है।

उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में एआई विकास पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन - एआई का महाकुंभ - को संबोधित किया

उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने आज गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय द्वारा एआईसीटीई और आउटलुक पत्रिका के सहयोग से नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित "एआई विकास - एआई का हाकुंभ" विषय पर आयोजित प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

उपराष्ट्रपति ने सभा को संबोधित करते हुए रेखांकित किया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब भविष्य की अवधारणा नहीं बल्कि वर्तमान की वास्तविकता है, जो स्वास्थ्य देखभाल निदान, जलवायु मॉडलिंग, शासन, शिक्षा, वित्त और राष्ट्रीय सुरक्षा सहित विभिन्न सेक्टरों को प्रभावित कर रही है।

राज्य सरकार पुलिस मॉडर्नाइजेशन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

■ गुजरात पुलिस में नवनियुक्त 11,607 उम्मीदवारों को चयन पत्र प्रदान किए गए

■ चयन पत्र केवल सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी, अनुशासन के पालन और राष्ट्र सेवा का संकल्प लेने का अवसर है - मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

-:मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल-:

■ पुलिस बल में नए शामिल होने वाले कर्मी भी 'नागरिक देवो भवः' के ध्येय को साकार करेंगे

■ जब कोई व्यक्ति संकट में होता है, तब सहायता के लिए सबसे पहले पुलिस को याद करता है

■ राज्यव्यापी सीसीटीवी नेटवर्क, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, बॉडी वॉर्न कैमरा, साइबर आश्वस्त - साइबर सेफ प्रोजेक्ट जैसे आयामों से पुलिस बल टेक्नॉलोजी संपन्न बना है

■ जब कोई नागरिक अपनी समस्या लेकर आए, तो उसके दुःख में सहभागी बनकर पूरे दिल से सहायक होना- उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

गांधीनगर, 23 दिसंबर :मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को राज्य पुलिस बल में नए चयनित युवा पुलिस कर्मियों को प्रेरित करते हुए कहा कि चयन पत्र केवल सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी, अनुशासन के पालन और राष्ट्र सेवा का संकल्प लेने का अवसर है।

पुलिस बल की भर्तियों में उत्तीर्ण होकर लगभग 3,100 युवतियों सहित 11 हजार से अधिक युवा 'टीम गुजरात' शामिल हुए हैं।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, राज्य मंत्री श्री

कमलेशभाई पटेल, गांधीनगर की महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, विधायक श्रीमती रीटाबेन पटेल सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में गांधीनगर में चयन पत्र प्रदान किए।

मुख्यमंत्री ने इन युवा एवं उत्साहवर्धक नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को मानव सेवा के धर्म और राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए सदैव कर्तव्यरत रहने की सीख दी।

इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि कानून लागू कराने वाले पुलिसकर्मी को कर्तव्य पालन में मानवाधिकारों का सम्मान, संवैधानिक मूल्यों का पालन और निष्पक्षता बनाए रखना आवश्यक है।

जब कोई व्यक्ति संकट में होता है, तब सहायता के लिए सबसे पहले पुलिस को याद करता है, यह कहते हुए मुख्यमंत्री ने आचरण में विनम्रता, वाणी में मधुरता और कार्य में निष्ठा को पुलिस सेवा की प्राथमिकता बनाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए POLICE शब्द के विशेष अर्थ की विस्तृत व्याख्या की। उन्होंने कहा कि P यानी पोलाइट - जनता के प्रति हमेशा विनम्र और सहृदयभाव के साथ काम करता हो,

O यानी ऑबिडिएंट जो हमेशा - अधिकारियों की आज्ञा में रहकर ड्यूटी निभाता हो, L यानी लोयल, भारत के संविधान, नियम-कानून के प्रति वफादार रहकर, उसका पालन करते हुए कार्य करता हो,

I यानी इंटेलिजेंट - सदैव सतर्क और बुद्धिचातुर्य से कार्य करता हो,

C यानी करेजियस, किसी भी परिस्थिति में साहस न हारने वाला, हरेक फ्रंट पर वो लड़ने के लिए सज्ज हो, E यानी एन्थूजियास्टिक, उत्साही हो, जनता की सेवा एवं सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर हो, राष्ट्रहित सर्वोपरि का भाव हृदय में रखता हो।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिए पुलिस के इस मर्म को पुलिस बल में नए मिल होने वाले कर्मी भी 'नागरिक देवो भवः' के ध्येय के साथ चरितार्थ करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री ने स्मार्ट पुलिसिंग की प्रधानमंत्री की सोच को साकार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा पुलिसमॉडर्नाइजेशन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।

विकसित भारत- जी राम जी योजना से विकसित, गरीबीमुक्त और रोजगारयुक्त गांव बनेंगे- केंद्रीय मंत्री श्री चौहान

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान के नागौर में किसान सम्मेलन में की सहभागिता

केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा- मजदूरों को डराने और भ्रम फैलाने की साजिश रची जा रही है

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2,000 करोड़ रु. से अधिक राशि का स्वीकृति पत्र मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को सौंपा

प्रदेश के 5 लाख दुग्ध उत्पादकों के बैंक खातों में 151 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित

(जीएनएस)।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राजस्थान में नागौर की मेड़ता सिटी में वृहद किसान सम्मेलन में विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों के बैंक खातों में सहायता राशि हस्तांतरित

की। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश, राजस्व राज्य मंत्री श्री विजय सिंह, किसान आयोग के अध्यक्ष श्री सी. आर. चौधरी, सांसद सुश्री महिमा कुमारी, विधायक श्री लक्ष्मण राम जी कलरू भी उपस्थित रहे।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान ने पिछले 2 साल में विकास का नया इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की 12,600 सड़कों के निर्माण के लिए 2 हजार 89 करोड़ रुपये की धनराशि आज जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। श्री चौहान ने कहा कि राजस्थान में कृषि क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। ज्यादा उपज देने वाले जलवायु अनुकूल नई किस्म के बीज का निर्माण प्रदेश में तेजी से हुआ है। साथ ही उत्पादन की लागत कम करने की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 6,000 रुपये की धनराशि के साथ अतिरिक्त 3,000 रुपये की राशि देने का काम भी राज्य सरकार ने किया है।

विशाखापत्तनम में पेसा महोत्सव का ऊर्जा से भरपूर पेसा रन और दिनभर चले आदिवासी खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और आयोजनों के साथ शुभारंभ हुआ

(जीएनएस)।

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आज से दो दिवसीय पेसा महोत्सव (23-24 दिसंबर 2025) का शुभारंभ प्रतिष्ठित रामकृष्ण बीच पर पेसा दौड़ के साथ हुआ। पेसा महोत्सव पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है, जो पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के तहत जनजातीय समुदायों के स्वशासन और सशक्तिकरण का जश्न मनाता है, जिसमें पारंपरिक खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अधिनियम के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है

सुबह आयोजित पेसा दौड़ में सभी आयु वर्ग के लोगों, विशेषकर आदिवासी युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दौड़ को अर्जुन पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध भारतीय तीरंदाज सुश्री ज्योति सुरेखा वेन्नम ने पंचायती राज मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती मुक्ता शेखर, आंध्र प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान एवं पंचायती राज आयुक्त श्री मुत्यालाराजू रेवु, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास आयुक्त एवं निदेशक श्री वी.आर. कृष्ण तेजा मैलावरपु, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. एम. सुधाकर राव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। अधिकारियों ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए पेसा की भावना और अनुसूचित क्षेत्रों

में आदिवासी समुदायों के अधिकारों, सामुदायिक संसाधनों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करने तथा ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला।

पेसा रन के बाद पेसा महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन श्रीमती मुक्ता शेखर, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, डॉ. बिजय कुमार बेहरा, आर्थिक सलाहकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय और श्री वी.आर. कृष्णा तेजा मैलावरपु, आयुक्त एवं निदेशक (पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास), आंध्र प्रदेश सरकार ने किया। इस कड़ी में दिन भर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयोजन में शिल्प बाजार और खाद्य महोत्सव सहित प्रदर्शनी स्टालों में आदिवासी हस्तशिल्प और स्थानीय व्यंजन प्रदर्शित किए गए। कबड्डी और तीरंदाजी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। कबड्डी के सेमीफाइनल मैच दिन भर चले और तीरंदाजी प्रतियोगिताएं क्वालीफाइंग, एलिमिनेशन और मेडल राउंड के माध्यम से आगे बढ़ीं।

कार्यक्रम के पहले दिन के दूसरे भाग में कई पेसा राज्यों की टीमों ने आदिवासी खेलों का प्रदर्शन किया, जिसमें चोलो, येदु पेनकुलता, गेडी दौद, रस काशी, उप्पन्ना बारेलू, पिथूल, सिकोर, मल्लखंबा और चक्की खेल जैसे पारंपरिक स्वदेशी खेल प्रस्तुत किये गये।

सम्पादकीय

बांग्लादेश अब पूरी तरह अराजकता का शिकार

बांग्लादेश की अराजकता बांग्लादेश में एक के बाद एक इंकलाबी छात्रों की हत्याओं से जहां एक तरफ भारत के खिलाफ विरोध की आग भड़क गई है, वहीं हिन्दुओं के खिलाफ हिसा भी भड़की है। लेकिन तीसरी महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले चुनाव न कराने की मांग वही इंकलाबी छात्र करने लगे हैं जिन्होंने शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन किया था। उनकी मांग है कि जब तक उनके साथियों के हत्यारों को सजा नहीं हो जाती तब तक देश में चुनाव नहीं हो सकता। दरअसल बांग्लादेश मे पूरी तरह अराजकता का शिकार हो चुका है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है क्योंकि राजसत्ता को अनितिता का लकवा मार गया है इसलिए वह किकर्तव्यविमूढ़ हो चुका है। राजसत्ता की अपंगता के कारण ही वहां की पुलिस मजहबी गुंडों के सामने असहाय साबित हो रही है। इंकलाबी छात्रों की मौतें इस बात की सबूत हैं कि सियासी हिसा में कोई राजनेता सुरक्षित नहीं है। मजहबी संगठनों के कारण बांग्लादेश में ऐसा मातम पसरा है कि मोहम्मद यूनुस की काम चलाऊ सरकार अब हक्का-बक्का दिख रही है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि वह बांग्लादेश को संभालें वैसे! बांग्लादेश में राजनीति की तीन धाराएं है। पहली तो आवामी लीग है जो कि बांग्लादेश जमात- ए-इस्लामी की दुश्मन है क्योंकि 1971 के स्वतंत्रता संघर्ष में इन मजहबी संगठनों ने पाकिस्तान के सैनिकों की मदद की थी और फिर 1974 में जब शेख मुजीबुर्रहमान के खिलाफ बगावत हुई तब भी इन्हीं संगठनों ने सेना से मिलकर देश में लोकतंत्र का गला घोंटा था। एक चुनी हुई सरकार को हटाकर इन्हीं मजहबी संगठनों ने एक पुतले को सत्ता सौंप दी जो शासकीय कौशल में कभी निपुण माना ही नहीं जाता था। उसने सत्ता संभालते ही आवामी लीग के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करवाना शुरू कर दिया। इससे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पाटा युनूस से खफा है और उसके कार्यकर्ता भी युनूस के समर्थकों एवं मजहबी गुंडों से परेशान हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में एक और पाटा है बीएनपी यानि बांग्लादेश नेशनिलस्ट पाटा जिसकी नेता हैं खालिदा जिया। पूर्व प्राधानमंत्री खालिदा के पति जियाउर रहमान स्पष्ट रूप से शेख हसीना के पिता की हत्या में शामिल थे। चुल मिलाकर बीएनपी और बांग्लादेश जमात-एइस्लामी के संबंध पुराने हैं। लेकिन अब जितने कट्टरपंथी तत्व बीएनपी के समर्थक थे वे सभी सत्ता में रहने के लिए खालिदा जिया से भी दूरी बनाते दिख रहे हैं। अन्तर इतना ही कि आवामी लीग को उन्होंने प्रातिबंधित कर दिया है जबकि बीएनपी को चुनाव में हिस्सा लेने की छूट मिली है। सवाल यह है कि इंकलाबी छात्र नेताओं की मौत पर आहत जो लोग फरवरी में चुनाव न कराने की धमकी दे रहे हैं, वे हैं कौन? चुनाव टलने से किसको फायदा होगा, इतना तो वे लोग भी जानते हैं जिन्हें देश में लोकतंत्र से ही नफरत हो गई है। वे लोग बिल्वुल नहीं चाहते कि हसीना के बाद खालिदा के हाथों में सत्ता आ जाए। बांग्लादेश में इस वक्त जो भी चल रहा है, वह पाकिस्तान की आईएसआई के षडांत्र का परिणाम है। ठीक इसी तरह चुनाव के पहले पाकिस्तान में काफी हिसा की घटनाएं होती हैं। बैसाखी के सहारे जिस तरह पाकिस्तान में लोकतंत्र रेंग रहा है, ठीक उसी तरह का लोकतंत्र आईएसआई बांग्लादेश में भी देखना चाहती है। इसके लिए बांग्लादेश में भी वही हो रहा है जो पाकिस्तान में हो चुका है। पाकिस्तान आज जिस मजहबी सियासत की बुनियाद पर चलाता है, ठीक उसी तरह की स्थिति वह बांग्लादेश में भी पैदा कर रहा है। मतलब कि अल्पसंख्यकों का नरसंहार और लोकतंत्र के प्राति षडांत्र। पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश में युनूस के अतिरिक्त कोई भी भावी सरकार अनुवूल नहीं होगी।

अटल नेतृत्व, अविरत विकास : मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना के जरिये राज्य के 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों को मिल रहा है शिक्षा के साथ पोषण

- गुजरात सरकार की संवेदनशील योजना बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है : अहमदपुर प्राथमिक शालाचार्य
- योजना अंतर्गत बच्चों को दिया जाता है सुखडी, चना चाट, मिक्स दलहन, मिलेट का अल्पाहार
- मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना द्वारा प्रधानमंत्री के 'पढ़ाई भी, पोषण भी' के ध्येय को साकार कर रही है गुजरात सरकार

गांधीनगर, 23 दिसंबर : देश में सुशासन के मूल्यों को प्रोत्साहन देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री तथा भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती यानी 25 दिसंबर को 'सुशासन दिवस' के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने सुशासन के मूल्यों का अनुकरण करते हुए नागरिकों के सर्वांगीण कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरूआत की है। इनमें एक महत्वपूर्ण योजना है : मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना, जो बच्चों की शिक्षा के साथ उनका पोषण भी सुनिश्चित करती है। इस योजना का लाभ गुजरात के 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों को मिल रहा है।

बच्चों की शिक्षा के साथ उनके पोषण पर भी बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 'सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन के अलावा; मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना अंतर्गत ताजा एवं पौष्टिक नाश्ता दिया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप सरकारी स्कूलों के प्रति बच्चों का लगाव बढ़ा है और साथ ही बच्चों में पोषण के स्तर में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त; सरकारी स्कूलों में आधुनिक क्लासरूम, पानी, बिजली, शौचालय, स्वच्छता, ट्रांसपोर्टेशन सहित सुविधाएँ उपलब्ध कराने में कोई कमी न रह जाए; इसके लिए राज्य सरकार सदैव कटिबद्ध है।'

मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना ने सुशासन को दी नई दिशा

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अपने 3 वर्ष के कार्यकाल के दौरान सुशासन, सेवा एवं विकास के नए मानदंड स्थापित किए हैं। उन्होंने लोक कल्याणकारी योजनाओं द्वारा राज्य की जनता का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर सुशासन को नई दिशा दी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने 11 दिसंबर, 2024 को 'मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना' की शुरूआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सुपोषित गुजरात मिशन अंतर्गत सरकारी एवं अनुदानित प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को पीएम पोषण योजना के तहत दिए जाने वाले दोपहर के भोजन के अलावा

पौष्टिक अल्पाहार भी मिले।

मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना : 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों को मिल रहा है कैलोरी-प्रोटीनयुक्त अल्पाहार

पीएम पोषण योजनांतर्गत समाविष्ट सभी स्कूलों में उपस्थित रहने वाले विद्यार्थी 'मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना' अंतर्गत नियमित लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना अंतर्गत विद्यार्थियों को औसत 200 किलो कैलोरी तथा 6 ग्राम प्रोटीन से युक्त पौष्टिक अल्पाहार दिया जाता है। हाल में राज्य के *लगभग 32,265 प्राथमिक विद्यालयों के 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों को कैलोरी-प्रोटीनयुक्त अल्पाहार मिल रहा है।

विद्यार्थियों की स्कूल में उपस्थिति से लेकर उनके पोषण के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई

गांधीनगर की देहगाम तहसील की अहमदपुर प्राथमिक शाला में विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना का लाभ मिल रहा है। यह योजना किस प्रकार बच्चों के लिए लाभदायी सिद्ध हुई है; इस संबंध में शाला के आचार्य श्री हसमुखभाई पटेल ने कहा, 'मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना शुरू होने के बाद विद्यार्थियों की स्कूल में उपस्थिति से लेकर उनके पोषण के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में माता-पिता रोजमर्रा के कामों के लिए घर से बाहर जाया करते हैं। ऐसे में बच्चों को भोजन किए बिना स्कूल में आना पड़ता है। मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना शुरू होने से पहले स्थिति ऐसी थी कि कई बच्चे नियमित स्कूल नहीं आते और उनका पढ़ने में भी मन नहीं लगता। यह योजना शुरू होने के बाद विद्यार्थी नियमित स्कूल आने लगे हैं। इतना ही नहीं; इस योजना के कारण कुपोषित बच्चों की संख्या में भी उल्लेखनीय कमी आई है। विद्यार्थियों को अल्पाहार में दलहन (कठोळ) दिया जाता है, जिसके कारण उनका शारीरिक विकास भी हो रहा है। गुजरात सरकार की यह संवेदनशील योजना बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'पढ़ाई भी, पोषण भी' के ध्येय को साकार कर रही है गुजरात सरकार

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना अंतर्गत बच्चों को सुखडी (आटा-घी और गुड़-चीनी से बनने वाला खाद्यान्न), चना चाट, मिक्स दलहन, मिलेट का अल्पाहार दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना के लिए 617.67 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।

गुजरात पीएम पोषण योजना अंतर्गत भोजन के अलावा; बालवाटिका से कक्षा 8 तक के सभी विद्यार्थियों को अल्पाहार देने का निर्णय लेने वाला अग्रिम राज्य है। गुजरात सरकार इस पोषणोन्मुखी योजना के क्रियान्वयन द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'पढ़ाई भी, पोषण भी' के ध्येय को साकार कर रही है।

--

इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत के बाद लीबियाई आर्मी चीफ की दर्दनाक मौत, सामने आया पाक कनेक्शन

(जीएनएस)।

तुर्किए की राजधानी अंकारा में मंगलवार की रात एक दर्दनाक हादसे ने लीबिया के सैन्य नेतृत्व को हिलाकर रख दिया है। अंकारा से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक प्राइवेट जेट क्रैश हो गया, जिसमें लीबिया के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद अली अहमद अल-हद्दाद समेत कुल आठ लोगों की जान चली गई।

इस हादसे में जनरल हद्दाद के साथ लीबियाई सेना के चार अन्य सीनियर अधिकारी और विमान के तीन क्रू मेंबर भी मारे गए हैं। लीबियाई सरकार ने इस घटना को देश के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया है।

कैसे और कब हुआ हादसा?

यह हादसा उस वक्त हुआ जब लीबियाई प्रतिनिधिमंडल तुर्किए के साथ उच्च-स्तरीय रक्षा वार्ता खत्म करके वापस अपने देश लौट रहा था। तुर्किए के अधिकारियों के मुताबिक, फाल्कन-50 बिजनेस जेट ने अंकारा के एसेनबोगा हवाई अड्डे से रात करीब 8:30 बजे उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के लगभग 40 मिनट बाद ही विमान का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट

गया।

अधिकारियों ने बताया कि विमान में अचानक बिजली की खराबी (इलेक्ट्रिकल फॉल्ट) आ गई थी, जिसके बाद पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी थी, लेकिन लैंडिंग की कोशिश के दौरान विमान रडार से गायब हो गया और अंकारा से लगभग 70 किलोमीटर दूर हायमाना जिले के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

आर्मी चीफ के अलावा अन्य सैन्य कमांडर की मौत

इस दुर्घटना में मारे गए लोगों में जनरल अल-हद्दाद के अलावा लीबिया के कई बेहद अहम सैन्य कमांडर शामिल थे। मृतकों में लीबियाई जमीनी बलों के प्रमुख जनरल अल-फितौरी घरायबिल, सैन्य निर्माण प्राधिकरण के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल महमूद अल-कतावी, सेना प्रमुख के सलाहकार मोहम्मद अल-असावी दियाब और एक सैन्य फोटोग्राफर शामिल हैं।

घटना पर क्या बोले लीबिया के प्रधानमंत्री

लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल-हमीद दबीबाह ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में इन सभी अधिकारियों की मौत की पुष्टि करते हुए इसे एक 'दुखद दुर्घटना' और लीबिया के लिए एक बड़ा झटका करार दिया है।

जनरल अल-हद्दाद पश्चिमी लीबिया में सेना के सबसे बड़े कमांडर थे और वे देश की बंटी हुई सेना को एकजुट करने की संयुक्त राष्ट्र की कोशिशों में बहुत अहम भूमिका निभा रहे थे, इसलिए उनका जाना लीबिया की स्थिरता के लिए भी एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है। तुर्किए सरकार ने हादसे की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं और चार अभियोजकों की एक टीम गठित की है।

आर्मी चीफ की मौत का 'पाक कनेक्शन'

लीबिया के लिए पाकिस्तान के साथ हुई हालिया नजदीकी बेहद अशुभ साबित होती दिख रही है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के लीबिया दौरे के ठीक बाद देश को यह गहरा जख्म मिला है, जिसके चलते लोग इसे 'पाक कनेक्शन' और बदकिस्मती से जोड़कर देख रहे हैं।

जनरल मुनीर ने एक दिन पहले ही की मुलाकात

जनरल मुनीर ने एक दिन पहले ही लीबिया का आधिकारिक दौरा किया था, जो अब विवादों और अंधविश्वास के घेरे में है। बेनगाजी में हुई इस मुलाकात के दौरान मुनीर ने 'लीबियन नेशनल आर्मी' (छठअ) के प्रमुख फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तार और उनके डिप्टी सद्दाम हफ्तार के साथ एक बड़ी डिफेंस डील पक्की की थी। इस समझौते के तहत पाकिस्तान को लीबिया को अपने फाइटर जेट्स देने थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस डील के तुरंत बाद ही लीबिया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और एक विमान हादसे में उन्हें अपने शीर्ष सैन्य नेतृत्व को खोना पड़ा।

नए साल में बड़ा धमाका करने को तैयार आयुष्मान खुराना, क्यों कहलाते हैं 'मिस्टर ROI'?

(जीएनएस)।

बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना ने 2025 में इंडस्ट्री के सबसे भरोसेमंद नामों में से एक होने की अपनी साख को पूरी तरह साबित किया है। उनके करियर की पहली फेस्टिवल रिलीज थामा ने 100 करोड़ क्लब में शानदार एंट्री की, जो आयुष्मान की पांचवीं 100 करोड़ की फिल्म होने के साथ-साथ उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनर भी बनी। जहां आयुष्मान हमेशा कंटेंट-ड्रिवन कहानियों के प्रति अपने लगाव को खुलकर स्वीकार करते हैं कि 'जहां आम आदमी हीरो होता है।'

तो वहीं अब वह नए साल में अपने काम को नौ नए स्तर पर ले जाने की तैयारी में हैं। 2026 में उनकी चार फिल्मों का दमदार लाइनअप है, जिन्हें सम्पूर्ण पारिवारिक मनोरंजन के तौर पर पेश किया जा रहा है। युष्मान ने कहा कि 'पोस्ट-पैंडेमिक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस का टेक्सचर पूरी तरह बदल चुका है और ऐसे समय में यह सफलता बेहद संतोषजनक लगती है। 'ड्रीम गर्ल 2' और'थामा' दोनों सफल रहीं।

2026 में लगातार दो 100 करोड़ की हिट फिल्मों के साथ कदम रखना मेरे लिए बेहद रोमांचक है।

नए साल की शुरूआत में मैं पति पत्नी और वो दो को लेकर उत्साहित हूं-यह एक साफ-सुथरी पारिवारिक कॉमेडी है और ऐसी फिल्मों की हमेशा जगह रहती है।

'सरल, विनम्र और मेहनती हैं सूरज बड़जात्या'

'इसके बाद सूरज बड़जात्या सर की अगली फिल्म है। बड़े निर्देशक होने के बावजूद वह बेहद सरल, विनम्र और उतने ही मेहनती इंसान हैं। जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित करती है, वह यह है कि वह सिनेमा के सच्चे विद्यार्थी हैं और पूरी लगन से काम करते हैं। मैं उनके पारिवारिक मनोरंजन सिनेमा का बड़ा फैन हूं। इस जॉनर में वह मास्टर हैं और आज के समय में इस तरह की फिल्मों की भारी कमी है। सूरज सर से बेहतर यह कोई नहीं कर सकता।'

'आज के दौर की भीड़ से बिल्कुल अलग'

'उनकी फिल्म में जो बात मुझे सबसे ज्यादा उत्साहित करती है, वह यह है कि हीरो सिर्फ एक किरदार नहीं होता, बल्कि पूरी फैमिली कहानी के केंद्र में होती है। यही बात इसे खास बनाती है। सूरज बड़जात्या की फिल्म में लीडिंग मैन एक क्विटेसेंशियल 'ग्रीन फ्लैग' होता है, जो आज के दौर की भीड़ से बिल्कुल अलग और ताजगी भरा एहसास देता है।

मैं आमतौर पर ऐसे किरदार निभाता हूं जो खामियों से भरे होते हैं और समय के साथ बदलते हैं, लेकिन यह फिल्म अलग है-यह एक आदर्श, सशक्त परिवार को हीरो के रूप में प्रस्तुत करती है। ऐसी फैमिली को पर्दे पर देखना प्रेरणादायक और बेहद भावनात्मक होगा।'

बॉलीवुड के 'मिस्टर आरओआई' कहलाते हैं

इसके बाद आयुष्मान 2026 की शुरूआत में अपनी अनटाइटल्ड और बेहद चर्चित वायआरएफ-पोशम पा प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू करेंगे।

इसके अलावा उनकी 'धर्मा सिख्या' फिल्म भी रिलीज होगी-जो हिंदी सिनेमा में एक अनोखी स्पाई कॉमेडी मानी जा रही है और जॉनर ब्रेकर बताई जा रही है।

आयुष्मान इस बात से खुश हैं कि वह हमेशा अपने निमार्ताओं के लिए सुरक्षित साबित होते हैं, खासकर उन फिल्मों की लागत को देखते हुए जिनका वह हिस्सा बनते हैं। यही वजह है कि उन्हें बॉलीवुड का 'मिस्टर आरओआई' कहा जाता है।

'मैं एक प्रोड्यूसर-फ्रेंडली एक्टर'

आयुष्मान ने कहा कि 'मैं एक प्रोड्यूसर-फ्रेंडली एक्टर हूं। जब मैं किसी प्रोजेक्ट के लिए कमिट करता हूं और शूट पर जाता हूं, तो चीजों को सरल रखने की कोशिश करता हूं-यहां तक कि अपनी एंटॉरेज के साथ भी।

नए साल में सबसे ज्यादा रहेगी इन मेहंदी डिजाइन्स की डिमांड

(जीएनएस)।

साल 2025 अब विदाई की ओर है और 2026 की खुशबू फिजाओं में घुलने लगी है। नए साल के आगाज के साथ ही शादियों का सीजन भी परवान चढ़ेगा। फैशन की दुनिया में जिस तरह कपड़ों के ट्रेंड बदलते हैं, ठीक वैसे ही मेहंदी डिजाइनों में भी बड़े बदलाव आने वाले हैं।

अगर आपके घर में भी 2026 में शहनाई बजने वाली है, तो अपनी हथेलियों को सजाने के लिए इन ट्रेंडिंग डिजाइनों पर एक नजर जरूर डालें।

ट

1. गोल टिक्की डिजाइनः सादगी के साथ 'रॉयल लुक'

पिछले कुछ सालों से 'गोल टिक्की' मेहंदी ने फिर से वापसी की है और 2026 में भी यह ट्रेंड टॉप पर रहेगा। यह डिजाइन दिखने में जितना सिंपल है, रचने के बाद उतना ही ग्रेसफुल लगता है।

जो लड़कियां मेहंदी पसंद नहीं करतीं, उनके लिए गोल टिक्की एक 'क्लासिक चॉइस' है। ऑफिस पार्टी हो या नए साल का जश्न, यह हर मौके पर जंचता है।

2. एवरग्रीन फ्लोरल डिजाइनः फूलों की खुशबू अब हाथों पर

फूलों के बिना श्रृंगार अधूरा है। 2026 में फ्लोरल मेहंदी का क्रेज और भी बढ़ने वाला है। आने वाले साल में बारीक फूलों की जगह 'बोल्ड' और बड़े फूलों के मोटिफ्स ट्रेंड में रहेंगे।

ब्राइडल मेहंदी में भी अब गुलाब और लोटस (कमल) के बड़े डिजाइनों को प्राथमिकता दी जा रही है, जो फोटो में बेहद शानदार दिखते हैं।

3. मिनिमलिस्टिक मेहंदीः 'लेस इज मोर' का जमाना

मॉडर्न जनरेशन अब मिनिमल डिजाइन की दीवानी है। 2026 में हैवी

मेहंदी की जगह सलीके से बेल या छोटी आकृतियां बनाने का चलन रहेगा।

इसमें हथेली का काफी हिस्सा खाली छोड़ा जाता है, जिससे डिजाइन उभर कर आता है। वर्किंग वुमन और यंग गर्ल्स के बीच फिंगर मेहंदी (सिर्फ उंगलियों पर डिजाइन) और ब्रेसलेट स्टाइल मेहंदी काफी पॉपुलर होगी।

4. मोर वाली मेहंदीः परंपरा और स्टाइल का मिलन

भारतीय शादियों में पीकॉक डिजाइन का एक अलग ही मुकाम है। 2026 में मोर के डिजाइन में कुछ नए कट्स और शेडिंग देखने को मिलेगी।

दुल्हनों के लिए मोर वाली मेहंदी को बारीक जाल वर्क के साथ कस्टमाइज किया जाएगा। यह पारंपरिक लुक को एक नई ऊंचाई देता है।

5. अरेबिक और इंडो-वेस्टर्न का फ्यूजन

नए साल में अरेबिक मेहंदी और पारंपरिक राजस्थानी मेहंदी का मिश्रण भी देखने को मिलेगा। इसे 'इंडो-वेस्टर्न' टच देकर और भी अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है, जिसमें स्पेसिंग और डार्क आउटलाइन का बेहतरीन इस्तेमाल होता है।

कोहरे की चपेट में उत्तर भारत, पटना में टूटा ठंड का रिकॉर्ड, 4 राज्यों में बारिश की आशंका

(जीएनएस)।

पूरा उत्तर भारत इस वक्त ठंड से बुरी तरह से कांप रहा है, कोहरे और शीतलहर ने लोगों का जीना मुहाल किया है तो वहीं दूसरी ओर भारतीय मौसम विभाग का ताजा अपडेट लोगों को काफी परेशान करने वाला है क्योंकि आईएमडी ने कहा कि 4 राज्यों में बारिश की आशंका है, जिससे कंपकपी बढ़ेगी।

आईएमडी ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका व्यक्त की है जिससे तापमान में तेजी से गिरावट आ सकती है और गलन बढ़ेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि 28 दिसंबर तक मौसम का यही हाल रहेगा। कई राज्यों में 'कोल्डवेव' जैसी

स्थिति दिख रही है, जिसकी वजह से लोगों को सेहत के प्रति सचेत रहने की जरूरत है।

दिल्ली-एनसीआर और आसपास के मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। दृश्यता कम होने के वजह से लोगों को आने-जाने में दिक्कत हो रही है। कोहरे के कारण फ्लाइट की उड़ानों में देरी हो रही है तो वहीं कई ट्रेनें भी अपने निर्धारित वक्त से काफी लेट चल रही हैं। दिल्ली-एनसीआर में हवा बेहद शुष्क है और अदकबहुत ज्यादा खराब है लेकिन दिन में यहां पर धूप निकलेगी। तापमान अधिकतम लगभग 18-19°C व न्यूनतम लगभग 11°C रहेगा।

दिल्ली के प्रमुख स्टेशनों में आज AQI निम्नलिखित है। (सुबह 5 बजे की स्थिति)

पूसा, दिल्ली -455 अदक

शादीपुर, दिल्ली -447 AQI

पंजाबी बाग, शिवाजी पार्क -439 AQI

नॉर्थ कैंपस, दिल्ली मिल्क स्कीम कॉलोनी -438 AQI

ERY मुंडका, दिल्ली -431 AQI

बिहार में टूटा ठंड का रिकॉर्ड

पटना में मंगलवार को सबसे सर्द दिन रहा, कल यहां दिन में तापमान 14 डिग्री पहुंचा गया था, यहां सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

क्यों दम घोंट रही है दिल्ली-एनसीआर की हवा? कब तक लागू रहेंगी जीआरएपी-4 की पाबंदियां?

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (NCR) में सर्दी की दस्तक के साथ ही प्रदूषण ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को दिल्ली की हवा अचानक 'बेहद खराब' से 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई। बुधवार, 24 दिसंबर को भी हालत काफी खराब बने हुए हैं।

आसमान में धुंध और धुएं की ऐसी मोटी परत छाई हुई है। दिन में भी विजिबिलिटी कम है और लोगों को सांस लेने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, सुबह दिल्ली का औसत AQI 412 दर्ज किया गया।

इन इलाकों में रेड अलर्ट

दिल्ली के 40 में से 26 स्टेशनों पर हवा 'गंभीर' श्रेणी में रही। सबसे बुरा हाल इन इलाकों का रहाः

नेहरू नगरः 465, मुंडकाः 457, चांदनी चौकः 453, ओखलाः 452

जहांगीरपुरीः 450+

नोएडा बना देश का सबसे प्रदूषित शहर

हैरानी की बात यह है कि मंगलवार को पूरे देश के 230 शहरों में से नोएडा की हवा सबसे ज्यादा जहरीली रही। नोएडा का AQI 426 दर्ज किया गया, जिसने प्रदूषण के मामले में दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया।

आखिर क्यों दम घोंट रही है हवा?

विशेषज्ञों के अनुसार, प्रदूषण बढ़ने के पीछे मुख्य रूप से दो कारण हैंः

मौसम की मारः सुबह के समय 100% नमी और घना कोहरा (Fog) होने के कारण प्रदूषक कण जमीन के करीब ही दबकर रह गए हैं। हवा की रफ्तार कम होने से ये कण फैल नहीं पा रहे हैं।

प्रदूषण के स्रोतः आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के प्रदूषण में सबसे बड़ा हिस्सा वाहनों (14.4%) का है। इसके बाद उद्योगों (7.2%) और निर्माण कार्यों (2%) का नंबर आता है।

NCR का असरः पड़ोसी जिलों का भी दिल्ली की हवा पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। झज्जर से 12%, सोनीपत से 6% और गाजियाबाद से करीब 2.7% प्रदूषण का योगदान दर्ज किया गया।

GRAP-4 की पाबंदियां और सावधानी

हालात को देखते हुए दिल्ली-NCR में ग्रैप-4 (GRAP-4) के सख्त नियम लागू हैं। पुराने (इर-3 पेट्रोल और इर-4 डीजल) वाहनों पर रोक है। बड़े निर्माण कार्यों पर पूरी तरह प्रतिबंध है। स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं बंद कर दी गई हैं ताकि बच्चों को जहरीली हवा से बचाया जा सके।

सेहत का रखें ख्याल

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR

तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में संशोधन

मुंबई,

रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निदेशों के अनुसार, पश्चिम रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू करने जा रही है। अब तत्काल टिकट केवल सिस्टम द्वारा जनरेट किए गए वन टाइम पासवर्ड (OTP) के प्रमाणीकरण के बाद ही जारी किए जाएंगे। यह ओटीपी टिकट बुकिंग के समय यात्री द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा तथा ओटीपी के सफल सत्यापन के पश्चात ही टिकट जारी किया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ओटीपी आधारित तत्काल प्रमाणीकरण प्रणाली पहले ही पश्चिम रेलवे से प्रारंभ होने वाली 21 ट्रेनों में लागू की जा चुकी है। अब यह ओटीपी आधारित तत्काल प्रमाणीकरण प्रणाली 24 दिसम्बर, 2025 से निम्नलिखित चार और ट्रेनों में भी लागू की जा रही है:-

1. ट्रेन संख्या 14702 बांद्रा टर्मिनस - श्री गंगानगर एक्सप्रेस
2. ट्रेन संख्या 19037 बांद्रा टर्मिनस - बरौनी एक्सप्रेस
3. ट्रेन संख्या 19483 अहमदाबाद - सहरसा एक्सप्रेस
4. ट्रेन संख्या 22956 भुज - बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस

यह नई प्रणाली कम्प्यूटरीकृत पीआरएस काउंटरों, अधिकृत एजेंटों, आईआरसीटीसी वेबसाइट तथा आईआरसीटीसी मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाने वाली तत्काल बुकिंग पर लागू होगी। इस बदलाव का उद्देश्य तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा वास्तविक यात्रियों को तत्काल टिकट प्राप्त करने में बेहतर सुविधा प्रदान करना है।

यात्रियों को सलाह दी जाती है कि बुकिंग के समय एक वैध एवं सुगम मोबाइल नंबर अवश्य प्रदान करें, ताकि ओटीपी सत्यापन प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। पश्चिम रेलवे सभी यात्रियों से इस महत्वपूर्ण बदलाव पर ध्यान देने का आग्रह करती है।

विकसित भारत - रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) : वीबी - जी राम जी (विकसित भारत - जी राम जी) अधिनियम, 2025 की प्रमुख विशेषताएँ

1. प्रस्तावनाः विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप समृद्ध एवं सुदृढ़ ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास, अभिसरण और संतृप्ति को बढ़ाकर तथा इससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिनों की मजदूरी-रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान कर; एक ग्रामीण विकास रूपरेखा स्थापित करने के लिए अधिनियम।

2. विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप बढ़ी हुई आजीविका गारंटीः अकुशल शारीरिक श्रम करने इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिनों की मजदूरी-रोजगार की वैधानिक गारंटी प्राप्त होगी।

3. अधिनियम के अंतर्गत शुरू किए जाने वाले कार्यः इस विधान के अंतर्गत शुरू किए जाने वाले सभी कार्य एवं परियोजनाएँ विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक का अंग होंगी, जिनमें जल-संबंधी कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा, मूलभूत अवसंरचना, आजीविका-संबंधी अवसंरचना तथा प्रतिकूल मौसमीय घटनाओं के शमन हेतु कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

4. कार्यों की आयोजनाः कार्यों की आयोजना विकसित ग्राम पंचायत आयोजना के माध्यम से की जाएगी, जिन्हें ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार किया जाएगा तथा इन्हें पीएम गति-शक्ति सहित राष्ट्रीय स्थानिक योजना प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जाएगा। पंचायतों की भौगोलिक स्थिति, नगरीकरण की दिशा में प्रगति आदि पर आधारित उनकी विविध विकासात्मक आवश्यकताओं को योजना निर्माण के दौरान ध्यान में रखा जाएगा।

5. कृषि के व्यस्ततम समय के दौरान पर्या कृषि श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करनाः ग्रामीण कार्यबल के लिए बढ़ाई गई मजदूरी-रोजगार गारंटी को दृष्टिगत रखते हुए, विशेष रूप से बुवाई और कटाई के व्यस्ततम समय के दौरान, कृषि श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इस संदर्भ में, अधिनियम में राज्यों को एक वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर साठ दिन की अवधि अधिसूचित करने का प्रावधान होगा, जिसके अंतर्गत बुवाई एवं कटाई की व्यस्ततम समयावधि को सम्मिलित किया जा सकेगा तथा इस अवधि में इस अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित कार्य नहीं किए जाएंगे।

6. योजना का स्वरूपः यह योजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में लागू की जाएगी। अधिनियम में विनिर्दिष्ट अनुसार, राज्य अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से छह माह के भीतर योजना को अधिसूचित करेंगे।

7. वित्तपोषण पद्धतिः केन्द्र सरकार और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारों के बीच निधि-साझेदारी की पद्धति पूर्वोत्तर राज्यों तथा हिमालयी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रोंके लिए 90:10 तथा अन्य राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 60:40 होगी।

8 केन्द्र सरकार, वस्तुनिष्ठ मानकों वाले एक संयुक्त सूचकांक के आधार पर प्रत्येक राज्य को मानक आधारित आवंटन करेगी और मानक आवंटन से अधिक व्यय की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होगी।

9. विशेषछूटः प्राकृतिक आपदाओं अथवा असाधारण परिस्थितियों के समय, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया जाए, विशेष छूट की अनुमति होगी, जिससे समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके एवं राहत हेतु प्रावधानों में अस्थायी संशोधन किया जा सके।

10. कार्यान्वयन संरचनाः राष्ट्रीय स्तर की एक संचालन समिति योजना का समग्र पर्यवेक्षण करेगी तथा मानक आवंटनों के अनुमोदन एवं अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अन्य कार्यों के लिए उत्तरदायी होगी। राज्य संचालन समिति को राज्य में योजना के कार्यान्वयन का क्षेत्राधिकार होगा तथा यह राष्ट्रीय स्तर पर जारी निदेशों के अनुरूप राज्य-विशिष्ट पर्यवेक्षण, निगरानी एवं नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

11. जिलाकार्यक्रमसमन्वयकः जिला कार्यक्रम समन्वयक,जिला स्तर पर योजना के अंतर्गत सभी कार्यकलापों के योजना-निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी एवं समन्वय के लिए प्राधिकृत अधिकारी होगा, जिसमें संबंधित सभी लाइन विभागों एवं प्राधिकरणों के साथ समन्वय शामिल होगा। ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी, योजना के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें यथा विहित रोजगार मांगों की पूर्ति एवं प्रबंधन, कार्यस्थलों का प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण तथा सहभागितापूर्ण योजना-निर्माण प्रक्रियाओं का सुगमीकरणसम्मिलित है। ग्राम पंचायत ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करने, विकसित ग्राम पंचायत योजनाएँ तैयार करने तथा अधिनियम में विहित अन्य कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगी।

12. पंचायतीराज संस्थाओं (पीआरआई) की भूमिकाः ग्राम पंचायत की प्राथमिक कार्यान्वयन भूमिका होगी तथा वह श्रमिकों का पंजीकरण करने, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करने तथा कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर कम से कम 50 प्रतिशत कार्यों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगी। ग्राम सभा नियमित सामाजिक अंकेक्षण भी करेगी।

वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 14वें दौर में उत्साहजनक भागीदारी देखने को मिली; 24 कोयला ब्लॉकों के लिए 49 बोलियां प्राप्त हुई

(जीएनएस)।

कोयला मंत्रालय के नामित प्राधिकरण ने आज वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 14वें चरण के लिए बोलियां आमंत्रित कीं। बोली प्रक्रिया में उद्योग जगत के हितधारकों की उत्साहजनक भागीदारी देखी गई। इस चरण में 41 ब्लॉक में से 24 ब्लॉक के लिए बोलियां प्राप्त हुईं। इससे देश के वाणिज्यिक कोयला खनन ढांचे में उद्योग की निरंतर रुचि का पता चलता हैं।

ऑनलाइन बोलियों को डिक्रिप्ट किया गया और बोलीदाताओं की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोला गया। इसके बाद, ऑफलाइन बोली दस्तावेजों वाले सीलबंद लिफाफे भी बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोले गए। पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया को बोलीदाताओं के लिए स्क्रीन पर लाइव प्रदर्शित किया गया। इस दौर में, 41 कोयला ब्लॉक में से 24 कोयला ब्लॉक के लिए 49 बोलियां प्राप्त हुई हैं।

नीलामी प्रक्रिया में वाणिज्यिक कोयला खनन व्यवस्था के तहत पहली बार बोली लगाने वाली पांच नई कंपनियों सहित कुल 11 कंपनियों ने भाग लिया। वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक नीलामी में नई कंपनियों की भागीदारी नीतिगत ढांचे में बढ़ते विश्वास और देश के कोयला क्षेत्र में बढ़ रहे अवसरों को दर्शाती है। भारत के विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ने के साथ-साथ कोयला क्षेत्र आर्थिक गति का एक प्रमुख चालक बना हुआ है।

अब बोलियों का मूल्यांकन एक बहु-विषयक तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को एमएसटीसी पोर्टल पर आयोजित होने वाली इलेक्ट्रॉनिक नीलामी में भाग लेने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक की नीलामी के प्रति निरंतर मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया औद्योगिक विकास को समर्थन देने, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में योगदान देने में कोयला क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।

देशभर में आस्था का प्रसार करते हुए, डाक विभाग ने भगवान श्री राम की एक अमूल्य तंजावुर कृति को बेंगलुरु से अयोध्या पहुंचाया

(जीएनएस)।

विशेष और सटीक लॉजिस्टिक्स का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए, डाक विभाग ने अपनी लॉजिस्टिक्स डाक सेवा के जरिए भगवान श्री राम की एक अमूल्य तंजावुर कलाकृति को बेंगलुरु से अयोध्या तक सफलतापूर्वक पहुंचाया।

पारंपरिक तंजावुर कला शैली में निर्मित यह चित्र एक अमूल्य सांस्कृतिक कलाकृति है। सोने की नींव पर बहुमूल्य और बेशकीमती पत्थरों की जड़ाई वाले इस चित्र का असाधारण कलात्मक और विरासत महत्व है। इस पवित्र कलाकृति को बेंगलुरु की श्रीमती जयश्री फनीश ने अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को दान किया था।

बारह फीट ऊंची और आठ फीट चौड़ाई वाली तथा लगभग आठ किलोग्राम वजनी इस विशाल पेंटिंग को अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए लकड़ी के बक्से में कई परतों वाली बबल रैपिंग के साथ पेशेवर तरीके से पैक किया गया था। खेप का परिवहन निरंतर निगरानी में किया गया, और विभागीय अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान वाहन के साथ रहे।

इस कलाकृति को ले जाने वाला वाहन 17 दिसंबर 2025 को बेंगलुरु से रवाना हुआ और लगभग 1,900 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 22 दिसंबर 2025 को सुरक्षित रूप से अयोध्या पहुंच गया। क्रेन और विशेष उपकरणों का उपयोग करते हुए इसे वाहन पर चढ़ाने और उतारने का कार्य अत्यंत सावधानी से किया गया।

यह मिशन अपनी तरह का पहला उच्च मूल्य वाला लॉजिस्टिक्स डाक खेप है, जिसे कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित कई डाक सर्किलों के बीच घनिष्ठ समन्वय के माध्यम से अंजाम दिया गया। संभागीय प्रमुखों और वरिष्ठ डाक अधिकारियों ने बेंगलुरु-हैदराबाद-नागपुर-जबलपुर-रीवा-प्रयागराज-अयोध्या मार्ग पर इस कलाकृति की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी। यात्रा के अंतिम चरण में घने कोहरे के बावजूद, इस खेप को अत्यंत सावधानी से संभाला गया और सुरक्षित एवं सुचारू रूप से पहुंचाया गया।

कलाकृति के अयोध्या पहुंचने पर, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ के महासचिव श्री चंपत राय की उपस्थिति में पेंटिंग को औपचारिक रूप से तीर्थ क्षेत्र में सौंप दिया गया और स्थापित किया गया।

यह सफल अभियान विशेष, उच्च-मूल्य वाली लॉजिस्टिक्स को संभालने में भारतीय डाक की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है, और राष्ट्रीय विरासत तथा सांस्कृतिक संरक्षण के समर्थन में विश्वसनीयता, सुरक्षा और सेवा उत्कृष्टता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

नौकरी से इलाज तक, मोदी सरकार की ये 5 योजनाएं बनीं गेमचेंजर, आपको फायदा मिला या रह गए पीछे

(जीएनएस)।

साल 2025 अब अपने आखिरी दौर में है और यह साल केंद्र की मोदी सरकार के लिए कई मायनों में यादगार रहा। सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे अहम मुद्दों पर सरकार ने ऐसे फैसले लिए, जिनका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ा।

युवाओं के हाथ में काम देने से लेकर बुजुर्गों की इलाज की चिंता कम करने तक, इस साल लॉन्च और विस्तारित की गई योजनाओं ने 'सबका साथ, सबका विकास' के नारे को जमीन पर उतारने की कोशिश की। आइए नजर डालते हैं 2025 की उन 5 बड़ी सरकारी योजनाओं पर, जिन्होंने युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक को राहत देने का काम किया।

1. पीएम इंटर्नशिप स्कीम

2025 में युवाओं के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में रही पीएम इंटर्नशिप स्कीम। बजट के जरिए घोषित इस योजना को इसी साल लागू किया गया। इसका मकसद डिग्री लेने के बाद भी अनुभव की कमी से जूझ रहे युवाओं को इंडस्ट्री रेडी बनाना है।

इस योजना के तहत देश की टॉप 500 कंपनियों में 12 महीने की इंटर्नशिप का मौका दिया जा रहा है। खास बात यह है कि इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को हर महीने 5,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलता है, जिसमें सरकार और कॉरपोरेट सेक्टर दोनों की हिस्सेदारी होती है। लाखों युवाओं के लिए यह योजना नौकरी की पहली सीढ़ी साबित हुई।

2. आयुष्मान भारत योजना का विस्तार

स्वास्थ्य के मोर्चे पर 2025 का सबसे बड़ा फैसला आयुष्मान भारत योजना का विस्तार रहा। सरकार ने 70 साल और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को इस योजना के दायरे में शामिल कर लिया।

इस फैसले की सबसे अहम बात यह है कि इसमें आय की कोई सीमा नहीं रखी गई। यानी 70 वर्ष से ऊपर का हर नागरिक अब 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करा सकता है। मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए यह योजना किसी संजीवनी से कम नहीं रही।

3. एनपीएस वात्सल्य योजना

2025 में सरकार ने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरूआत की। इस योजना के तहत माता-पिता अपने नाबालिग बच्चों के नाम पर पेंशन खाता खोल सकते हैं।

इस खाते में जमा राशि कंपाउंडिंग के जरिए बढ़ती रहती है और बच्चे के वयस्क होने पर यह खाता सामान्य एनपीएस में बदल जाता है। लंबे समय में यह योजना बच्चों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मददगार साबित हो रही है।

4. पीएम ई-ड्राइव योजना

पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने पुरानी फेम योजना की जगह पीएम ई-ड्राइव योजना लागू की। इसके तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और ई-बसों की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना से न सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ी, बल्कि शहरों में प्रदूषण कम करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाया गया।

5. प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान

2025 में सरकार ने आदिवासी समाज के विकास पर खास फोकस किया। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत देश के करीब 63,000 आदिवासी बहुल गांवों के कायाकल्प का लक्ष्य रखा गया है।

इन गांवों में पक्के घर, सड़क, बिजली, पेयजल और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का काम तेजी से शुरू हुआ। इससे आदिवासी इलाकों में शिक्षा और रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद जगी है।

6. बायो-राइड योजना

इन सबके अलावा 2025 में विज्ञान के क्षेत्र में भी एक अहम कदम उठाया गया। बायो-राइड योजना को मंजूरी देकर बायो-टेक्नोलॉजी और रिसर्च को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार ने बड़ा दांव खेला। इससे आने वाले वर्षों में मेडिकल और वैज्ञानिक शोध को नई गति मिलने की उम्मीद है।

कुल मिलाकर, साल 2025 में लाई गई ये योजनाएं सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि इनका असर आम लोगों की जिंदगी में साफ नजर आया। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आपको इन योजनाओं का फायदा मिला या आप अब भी इंतजार में हैं।

अंकिता केस को लेकर फिर गरमाई सियासत, कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी बोली-अपुष्ट एवं छेड़छाड़ का वायरल वीडियो

(जीएनएस)।

उत्तराखंड में एक बार फिर बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने एक कथित वायरल वीडियो सामने आने के बाद सीबीआई जांच की मांग की है। उधर भाजपा ने कांग्रेस पर शर्मनाक राजनीति करने का आरोप लगाया है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि अंकिता हत्याकांड मे वीआईपी का राग अलापने वाली कांग्रेस समय पर सुबूत मांगने पर पीठ दिखा गयी। उन्होंने कहा कि मामले मे अगर, कांग्रेस गंभीर होती तो अदालत मे साक्ष्यों के साथ बयान दे सकती थी।

कहा कि उस समय डीजीपी ने सार्वजनिक अपील की थी कि यदि किसी को वीआईपी के बारे में जानकारी है तो आए और बताये। तब किसी ने नहीं बताया और न आज बता रहे हैं। अंकिता पर अनावश्यक षड्यंत्र कर कांग्रेस उस बिटिया की आत्मा को अपमानित करने का भी काम कर रही है। वहीं अपुष्ट वायरल वीडियो को छेड़छाड़ वाला बताते हुए उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, ऐसे में उसे राजनैतिक हथियार बनाने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। जबकि जिस महिला का ऑडियो वायरल किया है उसके पिछले कृत्य और राजनैतिक षडयंत्र किसी से छिपा नहीं है।

भट्ट ने कहा कि कड़ी जांच का ही नतीजा है कि आरोपी अभी तक बेल पर बाहर नही आ पाए। अंकिता के परिवारजनों के मन के मुताबिक सरकारी वकील दिए और उनकी हर मांग को पूरा किया गया। कांग्रेस राजनीतिक स्टंटबाजों के चक्कर मे जिम्मेदार राजनैतिक दल की भूमिका का निर्वहन नही कर रही है। सरकार का प्रयास रहा कि अपराधियों को सख्त से सख़्त सजा मिले और ऐसी पैरवी की गई कि अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा हुई।

उन्होंने कहा कि वीडियो मे जिनके बयान और ऑडियो का जिक्र कांग्रेस के नेता कर रहे हैं वो रोज अपने बयान,अपने झगड़े और फिर समझौता और बयान बदलने के लिए जाने जाते हैं। भट्ट ने कहा कि कांग्रेस चुनाव से पहले वीआईपी के राग को अलाप कर अपनी नाकामयाबियों से ध्यान हटा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ही यह बताना चाहिए कि वीआईपी कौन है और उसने बयानबाजी के बजाय अदालत को जानकारी क्यों नही दी। अंकिता की असली अपराधी कांग्रेस ही है। जनता ने अंकिता कि लड़ाई लड़ने के लिए भाजपा को आशीर्वाद दिया है। कांग्रेस को दुष्प्रचार की ढाल को आधार बनाकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से बाज आने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया और आरोपियों को 24 घंटे के भीतर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मामले मे राजनीति करती रही कांग्रेस पहले भी इस पर मुँह की खा चुकी है और उसे फिर इसके लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा, जिस वायरल ऑडियो को राजनैतिक हथियार बनाने का अनैतिक कार्य कांग्रेस कर रही है, उसको लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। जिसमें ऑडियो बताए जा रहे एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उनकी आवाज के साथ अक की मदद से छेड़छाड़ कर यह ऑडियो तैयारी की गई है।

उन्होंने आरोपी के मोबाइल की जांच करने की मांग की है, उसपर कार्रवाई के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। इससे पूर्व ही संबंधित व्यक्ति ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही है और राजनैतिक साजिश के तहत, भाजपा की छवि खराब करने के मकसद से यह सब किया जा रहा है।

भट्ट ने सवाल उठाया कि बिना किसी ऑडियो की पुष्टि के कांग्रेस नेताओं द्वारा आरोप लगाना, उनकी अनैतिक राजनीति की पराकाष्ठा का एक और प्रमाण है। उनके नेताओं को अपनी ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान के लिए तत्काल सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए।

सीएम हेल्पलाइन शिकायत निपटाने के बदले10 हजार की रिश्वत, बीआरसी अमरवाड़ा के बीएसी रंगे हाथ गिरफ्तार

(जीएनएस)।

मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस की सख्ती लगातार जारी है। पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त श्री योगेश देशमुख के स्पष्ट निर्देश और पुलिस उप महानिरीक्षक मनोज सिंह के मार्गदर्शन में जबलपुर लोकायुक्त इकाई ने मंगलवार को छिंदवाड़ा जिले में एक बड़ी ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया।

इस कार्रवाई में ब्लॉक एकेडमिक समन्वयक (BAC) को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है।

10 हजार की रिश्वत लेते इफ्छ अमरवाड़ा के BAC रंगे हाथ गिरफ्तार

CM हेल्पलाइन शिकायत बना रिश्वत का जरिया

लोकायुक्त से मिली जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता कविता पीपरडे, पति डॉ. शेखर ब्रम्हने (उम्र 38 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 47, कैलाश विहार कॉलोनी, जिला छिंदवाड़ा हैं। कविता पीपरडे की समिति द्वारा संचालित यूनिक पब्लिक स्कूल, ग्राम सिंगोड़ी, तहसील अमरवाड़ा के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी।

इस शिकायत के निराकरण के एवज में सत्येन्द्र जैन (उम्र 51 वर्ष), पदस्थ ब्लॉक एकेडमिक समन्वयक (B.A.C), विकासखंड एकेडमिक समन्वयक कार्यालय (B.R.C), अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा द्वारा 10 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी।

रिश्वत लेते ही लोकायुक्त ने दबोचा

पीड़िता ने रिश्वत की मांग से परेशान होकर जबलपुर लोकायुक्त इकाई से संपर्क किया और पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत का सत्यापन होने के बाद लोकायुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कार्रवाई की।

दिनांक 23 दिसंबर 2025 को छिंदवाड़ा के इंडियन कॉफी हाउस, सर्कुलर रोड पर जैसे ही आरोपी सत्येन्द्र जैन ने शिकायतकर्ता से ₹10,000 की रिश्वत ली, लोकायुक्त टीम ने उसे मौके पर ही रंगे हाथ पकड़ लिया।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज

लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) की धारा 7, धारा 13(1)(इ), धारा 13(2) के तहत मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी से पूछताछ जारी है और जल्द ही उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।

ट्रैप दल में ये अधिकारी रहे शामिल

इस सफल ट्रैप कार्रवाई में लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने अहम भूमिका निभाई। ट्रैप दल में शामिल अधिकारी-

टीएलओ निरीक्षक राहुल गजभिये

निरीक्षक जितेन्द्र यादव

उप निरीक्षक शिशिर पांडेय

लोकायुक्त जबलपुर का अन्य स्टाफ

शिक्षा विभाग में रिश्वतखोरी पर सवाल

इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। उट हेल्पलाइन जैसी जनहितकारी व्यवस्था को रिश्वत का जरिया बनाए जाने से आम नागरिकों का भरोसा भी प्रभावित हो रहा है। लोकायुक्त की इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा।

लोकायुक्त की चेतावनी

लोकायुक्त पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी सरकारी कार्यालय में रिश्वत की मांग की जाती है, तो बिना भय के लोकायुक्त से शिकायत करें। पहचान गोपनीय रखी जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यूपी विधानसभा: सपा ने कहा कफ सिरप के आरोपी खेल रहे हैं फोटो का खेल, डिप्टी सीएम बोले हम उल्टा लटका देंगे

लखनऊ (जीएनएस)। विधान परिषद में कोडीन कफ सिरप मामले में चर्चा के दौरान पक्ष-विपक्ष ने एक-दूसरे पर खूब तीर चलाए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हर तरह के माफिया को उल्टा लकटाना हमारी जिम्मेदारी है। एक भी माफिया नहीं बचेगा। सपा के शाहनवाज खान ने कहा कि हम फोटो-फोटो खेल रहे हैं, वहीं कफ सिरप मामले में आरोपी जमानत पा जा रहे हैं।

शाहनवाज खान ने कार्यस्थगन प्रस्ताव के जरिये कहा कि इस घोटाले से जुड़े आरोपी उन्हें भी एक समारोह में मिले। हमसे ज्यादा उन्हें लोग घेरे खड़े थे। हमसे ज्यादा गाड़ियां उनके साथ थीं। सार्वजनिक जीवन में किसी के भी किसी के साथ फोटो हो सकते हैं। सपा के आशुतोष सिन्हा ने कहा कि शुभम जायसवाल तो छोटा पियादा है, इस घोटाले में सरकार के बड़े लोग शामिल हैं। शुभम को सुरक्षित पकड़कर लाया जाए। कहीं उसकी हत्या न करा दी जाए।

नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में क्राइम का ग्राफ काफी बढ़ गया है। पूरा प्रदेश दहशत में है। साइबर अपराध भी बहुत बढ़ गए हैं। उप मुख्यमंत्री व नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब तक साइबर अपराध के 87175 केस दर्ज हुए। 74824 मामलों का निस्तारण कराया गया है।

व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक में एसपी निर्देश, यातायात व अतिक्रमण पर जोर; रात्रि गश्त व सीसीटीवी स्थापना के दिशा-निर्देश

(जीएनएस)।

पीलीभीत,पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सीओ यातायात एवं नगर की ओर से मंगलवार को पुलिस लाइन में व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में व्यापारियों की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, अतिक्रमण हटाओ, सीसीटीवी स्थापना व रात्रि गश्त पर विस्तृत चर्चा हुई। अधिकारियों ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

बैठक में व्यापारी प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं रखीं। सीओ ने कहा कि शहर में बढ़ते अतिक्रमण से यातायात बाधित हो रहा, इसलिए नियमित अभियान चलाया जाएगा। रात्रि गश्त बढ़ाकर चोरी-डकैती रोकने पर जोर दिया। सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने व मेंटेनेंस के लिए व्यापारियों से सहयोग मांगा। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हेल्पलाइन 112 का उपयोग करने की सलाह दी।

एसपी ने निर्देश दिए कि व्यापारियों की सुरक्षा प्राथमिकता है। एक व्यापारी ने कहा कि यह पहल उनके कारोबार को मजबूत करेगी। बैठक से व्यापारियों में विश्वास बढ़ा।

मां ने बेटे की हत्या का आरोप लगाया, पुरानी रंजिश में पांच युवकों पर हमले का इल्जाम

(जीएनएस)।

पीलीभीत,थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के मोहल्ला बशीर खां में एक मां ने अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाते हुए पांच युवकों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। परिजनों का दावा है कि पुरानी रंजिश के चलते बेटे की बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शिकायत पर जांच शुरू कर दी।

मृतक रोहित (उम्र अज्ञात) 18 दिसंबर की रात करीब 9:30 बजे टहलने निकला था। देर रात न लौटने पर चिंतित परिजनों ने मिठाई दुकान पर काम करने वाले एक युवक को फोन किया। पहले इनकार करने के बाद उसने बताया कि रोहित को एक अन्य युवक उसके घर छोड़ गया। पहुंचने पर रोहित अचेत पड़ा था, सिर से खून बह रहा। परिजनों ने पूछताछ की व उसे घर ले आए।

19 दिसंबर को हालत बिगड़ने पर निजी चिकित्सक के पास ले जाया, लेकिन गंभीर चोटों से जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मां रजनी पत्नी शेर सिंह ने तहरीर में नामजद पांच युवकों पर पुरानी दुश्मनी में सिर पर वार कर हत्या का आरोप लगाया।

प्रभारी निरीक्षक नरेश त्यागी ने बताया कि तहरीर मिली, मामला गंभीर है। फॉरेंसिक जांच व गवाहों के बयान लिए जा रहे। आरोपी फरार हैं, तलाश जारी। परिजनों ने तत्काल न्याय की मांग की।

स्कूल जाते समय छात्रा को मिला फोन, महिला थाने में सौंपा; एसपी ड्राइवर का था,पुलिस ने की सराहना

(जीएनएस)।

पीलीभीत,थाना क्षेत्र में एक छात्रा ने इंसानियत दिखाते हुए रास्ते में पड़ा मिला फोन महिला थाने में जमा कर दिया। जांच में पता चला कि यह एसपी के ड्राइवर का था। पुलिस ने छात्रा की ईमानदारी की सराहना की और प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया।

मंगलवार दोपहर स्कूल जा रही कक्षा 10 की छात्रा ने रास्ते में एक मोबाइल फोन पाया। बिना छेड़छाड़ किए, उसने तुरंत महिला थाने पहुंचकर पुलिस को सौंप दिया। प्रभारी ने फोन की डिटेल चेक की, तो पता चला कि यह एसपी कार्यालय के ड्राइवर का था, जो रास्ते में गिर गया था। ड्राइवर को तुरंत फोन लौटा दिया गया।

महिला थाना प्रभारी ने छात्रा को सम्मानित करते हुए कहा कि ऐसी ईमानदारी समाज के लिए प्रेरणा है। एसपी ने भी सराहना संदेश जारी किया। छात्रा के परिवार ने कहा कि यह सिखाने वाली घटना है। पुलिस ने भविष्य में भी सहयोग की अपील की।

टप्पेबाजी गिरोह का पदार्फाश, गाजियाबाद-हापुड़ के चार ठग गिरफ्तार; 57 हजार लौटाए, 1.49 लाख चोरी का मामला

(जीएनएस)।

पीलीभीत,पुलिस व एसओजी टीम ने अंतरजनपदीय टप्पेबाजी गिरोह का भंडाफोड़ कर गाजियाबाद व हापुड़ के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरोह ने राजस्थान के ट्रक चालक-परिचालक को 1.49 लाख रुपये चुराए थे। पकड़े गए ठग हाईवे पर भोले-भाले लोगों को फंसाते थे।

मामला 13 दिसंबर का है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के जगमोहनपुर निवासी नारायण गुर्जर ने थाना सुनगढ़ी में शिकायत की। उनके परिचालक बहादुर गुर्जर को पीलीभीत में दो युवकों ने बातों में उलझाया, फिर ट्रक से 1 लाख 49 हजार 300 रुपये चुरा लिए। पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। एसपी के निर्देश पर एसओजी व सुनगढ़ी टीम बनी, जिसने सर्विलांस व मुखबिर से चारों को दबोच लिया।

गिरफ्तार नईमुद्दीन (विजय नगर, गाजियाबाद), मोहम्मद नूर उर्फ नूर खां (पिपलेहड़ा, हापुड़), सैफली (ईको गार्डन, पिपलेहड़ा) व इदुल हसन (विजय नगर, गाजियाबाद) ने पूछताछ में कबूल किया कि वे संगठित गिरोह चला रहे। पुलिस ने 57 हजार रुपये, चार मोबाइल व वारदात वाली कार बरामद की। प्रभारी निरीक्षक नरेश त्यागी ने कहा कि कानूनी कार्रवाई पूरी, गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी।

पीलीभीत: बीसलपुर में हिंदू महासभा का उग्र विरोध

बांग्लादेशी नेता यूनुस खान का पुतला दहन, दीपू चंद्र दास हत्याकांड पर आक्रोश; पूरे मार्ग में नारेबाजी

(जीएनएस)।

बीसलपुर (पीलीभीत)।* अखिल भारतीय हिंदू महासभा की बीसलपुर नगर इकाई ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ मंगलवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकताओं ने बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मुहम्मद यूनुस (यूनुस खान) का पुतला जलाकर आक्रोश जताया। प्रदर्शन पूरे बीसलपुर मार्ग से गुजरा, जहां "बांग्लादेश मुदार्बाद, यूनुस खान मुदार्बाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद" जैसे नारे गूंजे। कोतवाली चौराहा पहुंचकर पुतला दहन किया गया, जो हालिया घटनाओं से उपजे रोष को दर्शाता है।

प्रदर्शन का मुख्य कारण बांग्लादेश में सनातनी हिंदू दीपू चंद्र दास की कट्टरपंथी तत्वों द्वारा निर्मम हत्या है। आरोप है कि हत्या के बाद उनके शव को पेड़ से बांधकर जला दिया गया। इस घटना ने हिंदू समाज में गहरा आक्रोश फैला दिया। महासभा ने इसे अल्पसंख्यकों पर योजनाबद्ध हमलों का हिस्सा बताया। कार्यकताओं ने भारत सरकार से मांग की कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मुद्दा उठाया जाए व बांग्लादेशी घुसपैठ पर सख्ती बरती जाए। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन पुलिस ने सतर्कता बरती।

प्रदर्शन का नेतृत्व नगर महामंत्री महंत अवनीश रतन व युवा नगर अध्यक्ष दीपक मौर्य ने किया। उन्होंने कहा, "बांग्लादेश में हिंदुओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा, मंदिर तोड़े जा रहे व संपत्ति लूटी जा रही। प्रधानमंत्री व गृह मंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए।" नारेबाजी के जरिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई व हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की गई। यह विरोध देशव्यापी अभियान का हिस्सा है, जहां उत्तर प्रदेश के कई जिलों में समान प्रदर्शन हो रहे।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। नगर अध्यक्ष सुनील अवस्थी, नगर महामंत्री महंत अवनीश रतन, युवा नगर अध्यक्ष दीपक मौर्य, युवा नगर महामंत्री प्रतीक सक्सेना, वरिष्ठ नगर उपाध्यक्ष अनूप कुमार, नगर मंत्री महंत मुकेश गोस्वामी, नगर मंत्री रवि यादव, नगर उपाध्यक्ष शिवम गंगवार, कार्यालय प्रभारी पिंटू सक्सेना, अवधेश मिश्रा, प्रयास मिश्रा, पीयूष गंगवार, युवा नगर मंत्री सुखपाल मौर्य, बब्लू मौर्य, सर्वेश कश्यप सहित महिलाएं व युवा मौजूद रहे।

स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन का समर्थन किया, कहा कि वैश्विक हिंदू सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। महासभा ने आगामी दिनों में और कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की

विद्युत विभाग में अधिवक्ताओं से अभद्रता व जाति सूचक शब्दों का आरोप, अवैध वसूली का दावा

(जीएनएस)।

पीलीभीत,विद्युत विभाग के अधिवक्ताओं से अभद्रता, जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल व गला दबाकर जान से मारने की कोशिश का गंभीर आरोप लगा। सरकारी योजनाओं की जानकारी लेने पहुंचे अधिवक्ता संजय पांडे व जैतराम पासवान ने उपभोक्ताओं से अवैध वसूली व कर्मचारियों की मिलीभगत का दावा किया। कोतवाली में प्रदर्शन कर तहरीर दी, लेकिन एसडीओ गुप्ता ने सभी आरोप खारिज कर दिए।

मंगलवार दोपहर अधिवक्ता विभागीय कार्यालय पहुंचे, जहां विवाद भड़क गया। पीड़ितों के अनुसार, जानकारी मांगने पर एसडीओ व स्टाफ ने गाली-गलौज की, जातिसूचक टिप्पणी की व गला दबाकर हमला किया। संजय पांडे ने बताया कि यह अवैध वसूली के खेल को उजागर करने की कोशिश थी। तत्काल कोतवाली पहुंचकर प्रदर्शन किया, लिखित शिकायत में कार्रवाई की मांग की।

एसडीओ गुप्ता ने आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि अधिवक्ताओं ने कार्यालय में हंगामा मचाया व स्टाफ से मारपीट की, जिससे काम प्रभावित हुआ। कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए स्टाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गया। उच्चाधिकारियों को सूचित कर आदेश दिए। अधिवक्ता संगठन ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। एसपी ने मामले की जांच के

पीलीभीत: बीसलपुर नवीन मंडी भ्रष्टाचार का अड्डा बनी

मंडी सचिव के संरक्षण में बिचौलियों का धान तोलने का काला खेल, एक माह से किसानों का धान सड़ रहा; निस्तारण न होने से आक्रोश

(जीएनएस)।

बीसलपुर (पीलीभीत)। बीसलपुर नवीन मंडी में भ्रष्टाचार का पूरा खेल चल रहा है, जो किसानों की कमर तोड़ रहा। मंडी सचिव व एमो के इशारों पर बिचौलिये तौल में हेराफेरी कर किसानों का धान लूट रहे हैं। एक माह से मंडी में पड़ा किसानों का धान बिना निस्तारण के सड़ रहा है, जबकि बोली प्रक्रिया रुकी हुई। किसान संगठनों ने प्रशासन से तत्काल जांच व कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी। यह मामला जिले की अन्य मंडियों में फैले भ्रष्टाचार को भी उजागर कर रहा।

मंडी में धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (टरढ) पर होनी चाहिए, लेकिन बिचौलिये वजन कम दिखाकर किसानों को ठग रहे। एक किसान ने बताया, "हमारा 25 क्विंटल धान लाए, लेकिन तौल में 20 ही आया। बिचौलिये ने कहा कि नमी ज्यादा है, लेकिन वास्तव में उनका कमीशन कट रहा।" मंडी सचिव पर आरोप है कि वे बिचौलियों को संरक्षण दे रहे, जिससे पारदर्शिता नाममात्र की। स्टोरेज की कमी से धान खुले में पड़ा सड़ रहा, चूहों व मौसम से नुकसान हो रहा। पिछले हफ्ते 50 से अधिक किसानों ने शिकायत की, लेकिन मंडी अधिकारी ने टाल दिया।

कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1966 व उत्तर प्रदेश मंडी नियमावली के तहत तौल पारदर्शी होनी चाहिए, उल्लंघन पर 3 वर्ष कैद व जुमार्ना। लेकिन यहां इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों में छेड़छाड़ आम है। स्थानीय किसान नेता ने कहा, "मंडी सचिव के इशारों पर बिचौलिये 10-20% वजन कम करते, टरढ का लाभ किसान को नही मिलता।" एक माह से निस्तारण न होने से किसान कर्जदार हो रहे, कुछ ने निजी व्यापारियों को कम दाम पर बेच दिया। जिले में धान की फसल अच्छी हुई, लेकिन मंडी व्यवस्था फेल।

प्रशासन की लापरवाही से समस्या बढ़ रही। एसडीएम को शिकायतें मिलीं, लेकिन जांच टीम नही भेजी। किसान यूनियन ने जिलाधिकारी से मिलकर मांग की—मंडी सचिव का निलंबन, बिचौलियों पर मुकदमा व तत्काल निस्तारण। पूर्व में भी बीसलपुर मंडी में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, लेकिन कार्रवाई न हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल तौल व सीसीटीवी से पारदर्शिता आ सकती।

यह भ्रष्टाचार किसानों की मेहनत लूट रहा, खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो रही। यदि समय रहते अमल न हुआ, तो बड़े आंदोलन का अंदेशा। सरकार की 'किसान सम्मान' योजना पर सवाल खड़े हो रहे। (किसान हित!)

मिशन शक्ति-5 के तहत कोतवाली पुलिस ने छात्राओं को महिला अपराध व साइबर सुरक्षा पर जागरूक किया

(जीएनएस)।

पीलीभीत,एसपी के निर्देशन में मिशन शक्ति-5 अभियान के तहत थाना कोतवाली की पुलिस टीम ने मंगलवार को थाना क्षेत्र में भ्रमण कर छात्राओं को महिला संबंधी अपराधों व साइबर आपराधों की जानकारी दी। इस महिला सशक्तिकरण पहल से स्कूल व कॉलेज जाने वाली बालिकाओं में जागरूकता बढ़ी।

टीम ने विभिन्न स्कूलों व मोहल्लों का दौरा किया, जहां छात्राओं को छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना जैसे अपराधों से बचाव के कानूनी प्रावधान बताए। साइबर अपराधों पर फोकस करते हुए, सोशल मीडिया पर सतर्कता, अनजान मैसेज-लिंक से दूरी, ओटीपी गोपनीयता व संदिग्ध मामलों में हेल्पलाइन 1090 या 112 पर कॉल करने की सलाह दी। एक छात्रा ने कहा कि यह जानकारी उनके लिए उपयोगी साबित होगी।

एसपी ने बताया कि अभियान जिले भर में चल रहा, ताकि महिलाएं आत्मरक्षा में सक्षम हों। पुलिस ने ब्रोशर बांटे व संपर्क नंबर साझा किए। छात्राओं ने पुलिस की पहल की सराहना की।